शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 12 – 19 अगस्त 2024 मूल्य पांच रूपये

लैंड रेवेन्यू मैनुअल में बदलाव की तैयारी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के दोसड़का पुलिस मैदान

में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 तहसीलों के 10-10 पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित कर इस योजना की शुरुआत की। प्रथम चरण में 190 गावों के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किये जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के आबादी देह रकवा में भूमि मालिकों के कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाना है, जिससे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है।

इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गांवों में से 13,599 आबादी देह गांवों में से ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि जिला हमीरपुर सहित कुल 6314 गांव के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे, दूसरे स्तर के 774 गांवों के 1482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला हमीरपुर में 355 आबादी देह गांवों के अंतिम स्तर के नक्शे प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि हमीरपुर देश का पहला जिला बना है, जहां आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि लाल डोरा में रहने वाले को अधिकार मिलने से उनकी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही दिन से लोगों की सुविधा के लिए अनेक कार्य कर रही है। लैंड रेवेन्यू कोड में बदलाव लाया गया है, जिससे पिछले छः महीने 1.57 लाख इंतकाल किए गए है ताकि लोगों को बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे के लिए हर अधिकारी के स्तर पर समयसीमा तय कर दी गई है। लैंड रेवेन्यू मैनुअल में भी बदलाव किया जाएगा। इसके अतिरिद्र आने वाले समय में विभागीय कामकाज में अन्य बदलाव लाए जाएंगे ताकि लोगों को राजस्व कार्यालयों में बार-बार न आना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए साधन संपन्न लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए थे, जबकि वर्तमान राज्य सरकार गरीब परिवारों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। उन्होंने संपन्न परिवारों से सरकार की सब्सिडी स्वयं छोड़ने का आहवान किया, ताकि राज्य आत्मनिर्भर बन सके और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े होटल भी बिजली व पानी की सब्सिडी छोड़ने की पहल करे। उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता में सुधारने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है इसलिए 50 हजार से कम सालाना आय वाले परिवारों को ही पानी के बिल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास कर रही है और गांव में सुविधाएं बढ़ा रही है। प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेंहू को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा जाएगा और इसकी सर्टिफिकेशन भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों और दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भैंस के दूध को 55 रुपये प्रति लीटर तथा गाय के दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। कांगड़ा जिला के ढगवार में 250 करोड़ की लागत से आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपये की बढ़ौतरी कर 300 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ उठाना चाहिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाया है। इस वर्ष भी बादल फटने की घटनाओं में 31 लोग काल का ग्रास बने और 50 से ज्यादा लोगों अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, ताकि जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें।

वन-माफ़िया को कौन दे रहा है संरक्षण:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बंज़ार में सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़ों को काटने में मामले में सरकारी

संरक्षण का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तरह के माफिया सक्रिय हैं लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक तरफ़ देश में वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अभियान चला रही हैं दूसरी तरफ़ प्रकृति प्रदत्त जीवन देने वाले हरे-भरे पेड़ हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में काटे और बेचे जा रहे हैं। बार-बार स्थानीय लोगों द्वारा आवाज़ उठाने के बाद भी वन विभाग और प्रशासन अनजान बना हुआ है। आम लोगों के अलावा स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी के बार-बार आवाज़ उठाने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई। इससे यह साफ़ है कि वन माफिया पर सरकार में बैठे ताकतवर लोगों का हाथ है। इसलिए यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मुख्यमंत्री यह बताएं कि इस तरह से माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है। जो लोग इस खेल में शामिल हैं उन पर क्या कारवाई की जा रही है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में माफिया राज चल रहा है क़ानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी हैं। खनन माफिया से लेकर, स्क्रैप माफिया और वन माफिया का बोलबाला है। कभी स्क्रैप माफिया दिन दहाड़े गोली चला देता है, खनन माफिया पुलिस टीम पर हमला कर देता है तो वन माफिया वन विभाग की टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। हिमाचल प्रदेश वन निगम द्वारा एक ठेकेदार को सिराज डिवीज़न में आने वाले शुराग शिल्ह के जंगलों में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने का काम मिला था। लेकिन ठेकेदार द्वारा सूखे और उखड़े पेड़ों की कटान करने के बजाये हरे पेड़ों की धड़ल्ले से कटान की गई। इसके लिए कश्मीर से ख़ास श्रमिक बुलाए गए। यह सब प्रशासन की निगरानी में हुआ। डिमर-चाहड़ी के गोदाम में पांच से छः हज़ार से ज्यादा हरे पेड़ों के स्लीपर पड़े हुए हैं लेकिन ज़िम्मेदार आंखे बंद कर बैठे हैं। इस तरह के खुल हो रहे खेल में कौन-कौन शामिल हैं और उन्हें किस-किस का संरक्षण प्राप्त हो है। यह प्रदेश के सामने आना चाहिए। यह घटना बहुत गंभीर हैं और इस घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ़ क्या कारवाई की गई है, उसके बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए।

78वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर लेडी

गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्र को विदेशी साम्राज्य की गुलामी से आजादी मिली। उन्होंने कहा कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और वीर सपूतों के संघर्षो ने हमें आजादी दिलाई है।

राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशभक्तों को नमन करते हैं। हम उन वीर सपूतों को भी नमन करते हैं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

उन्होंने प्रदेश की उन्नति और सर्वांगीण विकास की कामना करते हुए कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम और अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं लगातार लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'एक बूटा मां के नाम' अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज भी भेंट किए।

लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला और राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल शिव प्रताप

शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वह एक महान नेता, प्रखर वक्ता थे और उन्होंने प्रत्येक पद पर रहते हुए सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने जीवन पर्यन्त मूल्य आधारित राजनीति की। राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए दी गई अमूल्य सेवाओं और बहुमूल्य योगदान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र सदैव याद रखेगा।

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के महान नायक थे। उनका कहना था कि 'छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता' राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में उनके शब्द और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। विशाल हृदय से ही समाज सेवा की जा सकती है। राष्ट्र हित के लिए वह सभी को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि आज देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी शुरूआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया।

विधायक बलबीर वर्मा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान एवं उप-महापौर उमा कौशल, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, पार्षदगण, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने साइबर अपराध के मामलों पर चिंता व्यक्त की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में पुलिस उप महानिरीक्षक मोहित चावला ने भेंट की और उन्हें राज्य में साइबर अपराध की स्थिति के बारे में अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश के नागरिकों को इस संबंध में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है और उन्हें ऐसे अपराध से सुरक्षित रहने के लिए शिक्षित व जागरूक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच करने वाले को देख रहे पुलिस कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे ऐसे मामलों को प्रभावी तरीके से निपटा सकें। उन्होंने साइबर अपराध को रोकने लिए साइबर अपराध टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। मोहित चावला ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि इस वर्ष अब तक साइबर पुलिस थानों में 83 मामले दर्ज किए गए हैं और 8,290 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि साइबर पुलिस थानों में दर्ज मामलों और शिकायतों का समाधान करते हुए शिकायतकर्ताओं को 2.51 करोड़ रुपये की राशि लौटाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर कमांडो का गठन किया जा रहा है और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल में एकीकृत किया गया है ताकि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर तुरंत और रियल टाइम में कारवाई की जा सके।

देशी गायों और भैंसों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने पर विचार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए उत्पादों के विशिष्ट ट्रेडमार्क के तहत ब्रांडिंग की जाए ताकि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल सकें। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए व्यापक तंत्र विकसित करने और राज्य में मिट्टी की जांच के लिए विशेष लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त खेती की पद्धति अपनाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि विभाग में युक्तिकरण के निर्देश देते हुए कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विभाग में खाली पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 फीसदी आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य सरकार का प्राथमिक क्षेत्र है और इसको प्रोत्साहित करने के लिए 2024-25 के बजट में विशेष पहल की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में कृषि विभाग और जल शक्ति विभाग, जाइका व शिवा परियोजनाओं के सहयोग से एकीकृत सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करेगा, ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिले और इन योजनाओं को व्यावहारिक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक कूहलों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करेगी। उन्होंने संबंधित जिलों में विशिष्ट फसल उत्पादन आवश्यकताओं के अनुसार कोल्ड स्टोर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाइका के तहत गेहूं और मक्का के भंडारण के लिए साइलो स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। भैंस और गाय के दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 55 और 45 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन और प्राकृतिक खेती दोनों ही संबद्ध गतिविधियां हैं, इसलिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती क्लस्टरों में देशी गायों और भैंसों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य की जलवायु डेयरी क्षेत्र के लिए सबसे अनुकूल है और इसका लाभ उठाकर किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है, जिससे उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को एकीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जाइका और मिल्कफेड के कामकाज की भी समीक्षा की और कार्य में डिजिटल पद्धति अपनाने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव कृषि सी. पालरासू, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक कृषि कुमुद सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

जाठिया देवी माउंटेन टाउनशिप परियोजना में उपलब्ध भूमि पर काम शुरू करने के निर्देश:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। नगर नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री व हिमुडा के अध्यक्ष राजेश धर्माणी ने जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप विकसित करने सम्बंधी कार्य की समीक्षा की। बैठक में हिमुडा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीईओ) व सचिव संदीप कुमार, हितधारकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों व अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हिमुडा अध्यक्ष ने सीईओ और कार्यकारी निदेशक को भूमि हस्तांतरण के संबंध में जिला के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए। राजेश धर्माणी ने प्रथम चरण में उपलब्ध भूमि पर कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि कार्य में प्रगति हो सके, जिससे इस परियोजना का इंतजार कर रहे लोगों तथा निवेशकों का विश्वास भी बढ़े। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उपरोक्त परियोजना का कार्य शुरू करते समय हरित पहल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा जाठिया देवी परियोजना तथा आर्यभट्ट भू-सूचना विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एजीआईएसएसी) प्रतिनिधियों द्वारा हिमुडा संपत्तियों की जियो टैगिंग पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

सीईओ संदीप कुमार ने माउंटेन टाउनशिप जाठिया देवी की नवीनतम प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्य अभियंता (निर्माण) डॉ. सुरेन्द्र कुमार वशिष्ट ने भारत सरकार को दी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और हिमुडा के कार्यकारी निदेशक ने जाठिया देवी में भूमि की नवीनतम स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगो की बेहद अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा।

पटवारी एवं कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण निष्ठा व समर्पण भाव से कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी और कानूनगो अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने देहरा में 78वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण जोश, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेशभर में राज्य, जिला और उप-मण्डल स्तर पर कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सकोह, आईआरबी पंडोह, उत्तराखंड आईआरबी सशस्त्र बल, ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी सपड़ी, गृहरक्षक, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइडस की टुकड़ियां शामिल हुई। परेड का नेतृत्व परिवीक्षाधीन आईपीएस कमांडर सचिन हीरेमठ ने किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणाएं की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता-पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा की। सरकार इन बच्चों का आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निःशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार पीजी आवास के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की सहायता भी प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 हजार जीएसटी विरासत मामलों के समाधान के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके। प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अथक प्रयासों के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में लगी हुई है और इस दिशा में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया गया है।

वर्तमान सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में 31 हजार रोजगार के अवसर सृजित किए हैं जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच साल में सिर्फ 20 हजार लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है जिनमें से ज्यादातर भर्तियां कानूनी विवादों में फंसी रही।

प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर इंतकाल अदालतों के माध्यम से 1 लाख 57 हजार 500 राजस्व मामले निपटाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कई संस्थाओं और शख्सियतों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने करदाताओं और व्यापारियों को विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले 'करदाता संवाद अभियान' की भी शुरुआत की। इसके अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग शिकायत निवारण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने जा रहा है जिसे करदाताओं और उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विभाग की दक्षता भी बढ़ेगी।

उन्होंने कार्य कुशलता बढ़ाने और काम में डिजिटल पद्धति अपनाने के लिए विभिन्न पंचायतों को लैपटॉप भी वितरित किए।

मरीजों को निजी अस्पतालों में 30 नवंबर तक मिलेगी डायलिसिस सुविधा

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना हिमकेयर में संशोधन किया गया है। योजना में संशोधन किए जाने से अब निजी अस्पताल मरीजों को 1 सिंतबर से 30 नवंबर, 2024 तक डायलिसिस सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अन्य प्रवधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित में यह फैसला लिया गया है ताकि गुर्दे की बीमारियों से ग्रसित मरीजों को डायलिसिस की निर्बाध सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हरसम्भव कदम उठाये जा रहे हैं।

भूखंडों की नीलामी के लिए ई-ऑक्शन पद्धति लागू करने के निर्देश:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने निर्देश दिए कि निगम के अंतर्गत औद्योगिक

क्षेत्र बद्दी, औद्योगिक एस्टेट दावनी तथा राज्य भर में अन्य स्थानों पर भूखंडों की नीलामी के लिए ई-ऑक्शन पद्धति को लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ाना है। उद्योग मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में निगम के 10.25 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ पर संतोष व्यक्त किया जोकि निगम की निरंतर उन्नति और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है।

राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बोर्ड को अवगत करवाया कि नई हिमरस बिल्डिंग का फेस लिफ्ट कार्य अत्याधुनिक डिजाइन के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने अवगत करवाया कि निगम ने औद्योगिक एस्टेट दावनी में भूमि के हस्तांतरण की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार के भूखंड विकसित किए जाएंगे और यह निगम की रणनीतिक विस्तार योजनाओं का हिस्सा होंगे।

बैठक के दौरान बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने निगम की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजनेस योजना और संसाधन पूर्वानुमान को भी मंजूरी दी। राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, प्रधान सचिव उद्योग आर. डी. नजीम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 696.47 करोड़ रुपये की लागत से नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 696.47 करोड़ रुपये की लागत से 11 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते

हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी 11 परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटक की आमद को बढ़ावा जिनका उद्देश्य राज्य में पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करता है। इसलिए राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाना और नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 161.91 करोड़ रुपये की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, पालमपुर और नगरोटा बगवां में सौंदर्यकरण कार्य 95.50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, नादौन में वेलनेस सेंटर में निर्माण पर 91.42 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। हमीरपुर जिले के बाबा बालकनाथ जी दियोटसिद्ध में पर्यटकों की सुविधा के लिए 65.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नादौन में 64 करोड़ रुपये की लागत से राफ्टिंग कॉम्पलेक्स का विकास, शिमला जिले के बनूटी में 58.37 करोड़ रुपये की लागत से वेलनेस सेंटर का निर्माण, मनाली में 45.25 करोड़ रुपये की लागत से वेलनेस सेंटर, धर्मशाला में 39.51 करोड़ रुपये की लागत से आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण, शिमला में 34.85 करोड़ रुपये की लागत से आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक का विकास, कुल्लू में 27.76 करोड़ रुपये की लागत से वेलनेस सेंटर का विकास तथा कुल्लू जिले में नग्गर कैसल के जीर्णोद्धार पर 11.57 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने तथा निर्धारित समयावधि में कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग डैम को अंतरराष्ट्रीय स्तर के 'बर्डज पैराडाइस' के रूप में विकसित किया जाएगा तथा यह जल क्रीड़ाओं के दृष्टिगत भी उत्कृष्टता का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, इससे क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया है तथा यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए आवश्यक पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा इस वर्ष जुलाई, 2024 तक राज्य में 1.13 करोड़ पर्यटक भ्रमण के लिए आ चुके हैं।

सेब मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत फलों के प्रापण के लिए दिशा-निर्देश जारी

शिमला/शैल। सचिव, उद्यान सी.पालरासु ने मण्डी मध्यस्थता योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत प्रापण किए जाने वाले फलों की गुणवत्ता को बनाए रखने और वास्तविक लाभार्थियों को योजना का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए।

उन्होंने कहा कि फलों का प्रापण बागवानों के पास उपलब्ध भूमि तथा फलदार पौधों के अनुपात के अनुसार किया जाएगा जिसके लिए बागवानों द्वारा उद्यान कॉर्ड लाना अनिवार्य होगा जिसका मिलान राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) से सम्बंधित प्रभारी फल एकत्रीकरण केंद्र द्वारा किया जाएगा। बागवानों से सेब फल सम्बंधित इलाके के फल एकत्रीकरण केंद्र में ही लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा सड़े-गले, पक्षियों द्वारा खाए हुए व दागी फल, स्कैबग्रस्त, इथरल स्प्रे किए हुए फल तथा 51 मिलीमीटर से कम डायामीटर वाले फल नहीं लिए जाएंगे और ऐसे फल एकत्रीकरण केंद्र से ही वापिस कर दिए जाएंगे। इस प्रकार के अवांछित फल किसानों द्वारा वापिस न लेने तथा केंद्र पर छोड़ कर जाने की स्थिति में उसे नष्ट करने के लिए केंद्र प्रभारी सक्षम होगा और बागवानों को इसका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फल एकत्रीकरण केंद्र पर सम्बंधित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा बागवानी विकास अधिकारी एवं बागवानी प्रसार अधिकारियों की आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए तैनाती की जाएगी।

बैठक में उद्यान विभाग, एचपीएमसी व हिमफैड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

सरकार के आर्थिक उपायों पर उठते सवाल

सुक्खू सरकार ने दिसम्बर 2022 में प्रदेश की सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालते ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर जनता को चेतावनी दी थी की हालत कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। इस चेतावनी के बाद पहले कदम के रूप में पिछली सरकार द्वारा अंतिम छः माह में लिये गये फैसले पलट दिये थे। पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाया। नगर निगम क्षेत्र में पानी गारबेज के रेट बढ़ाये। सरकार और मुख्यमंत्री को राय देने के लिए मुख्य संसदीय सचिवों, सलाहकारों और विशेष कार्याधिकारियों की टीम खड़ी की। सेवानिवृत नौकरशाहों की सेवाएं ली। सरकार पर उठते सवालों को व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र से शान्त करवा दिया। कर्ज लेने के जुगाड़ लगाये और हर माह करीब हजार करोड़ का कर्ज लेने की व्यवस्था कर ली। यह सब कर लेने के बाद अब पन्द्रह अगस्त को साधन संपन्न लोगों से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर तरह की सब्सिडी त्यागने का आग्रह किया है। सरकार के घोषित/अघोषित सलाहकारों ने जन सुविधाओं पर अब तक चलाई गई कैंची को सधे हुए कदम करार देकर इसकी सराहना की है। कांग्रेस के अन्दर जो स्वर कल तक कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर मुखर होते थे अब इस संद्धर्भ में एकदम चुप हैं। साधन संपन्नता की परिभाषा पचास हजार वार्षिक आय कर दी है। आज गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाला भी इस आय वर्ग में आ जाता है। जिस सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिये इस तरह के फैसले लेने पड़ जायें और उपाय सुझाने के लिए एक मंत्री स्तरीय कमेटी गठित हो उसके चिन्तन और चिन्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार सत्ता में है और उसे कार्यकाल तक सहना ही पड़ेगा।

सरकार के इन उपायों पर सवाल उठाने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि ऐसे फैसला राजनीतिक समझदारी से ज्यादा प्रशासनिक तंत्र की प्रभावी भूमिका की झलक प्रदान करते हैं। इन फैसलों की कीमत आने वाले वक्त में जनता और सत्ताधारी दल को उठानी पड़ेगी प्रशासनिक तंत्र को नहीं। यह फैसले उसे समय स्वतः ही बौने हो जाते हैं जब सरकार पर उठने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों का आकार इनसे कहीं बड़ा हो जाता है। नादौन में ई बस स्टैंड के लिये 6,82,04 520/- रुपए में खरीदी गयी जमीन के दस्तावेज इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। भ्रष्टाचार के इस मामले पर प्रशासनिक तंत्र राजनीतिक नेतृत्व और विपक्ष सब एक बराबर जिम्मेदार हैं। ऐसे में राजस्व आय बढ़ाने के लिये जनता की सुविधाओं पर कैंची चलाकर किये गये उपायों की विश्वसनीयता क्या और कितनी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदेश को बिजली राज्य बनाने की योजनाओं का आज कितना लाभ मिल रहा है? यही सवाल पर्यटन राज्य बनाने की योजनाओं पर है? पूरी उद्योग नीति पर उस समय स्वतः ही सवाल उठ जाते हैं जब यह सामने आता है कि उद्योगों की भेंट प्रदेश की वित्त निगम, खादी बोर्ड, एक्सपोर्ट निगम और एग्रो पैकेजिंग आदि कई निगमें भेंट चढ़ चुकी है और कई कगार पर खड़ी हैं।

हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिये यहां की कृषि और बागवानी तथा वन संपदा को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन इस और ध्यान दिया ही नहीं गया। स्व. डॉ. परमार की त्रीमुखी वन खेती की अवधारणा शायद आज के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र के लिए एक पहेली होगी। इसी अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान करने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इन विश्वविद्यालयों के अनुसंधान को खेत तक ले जाने का प्रयास सरकारों ने नहीं किया क्योंकि प्रशासन को मेहनत करनी पढ़नी थी। बागवानी विश्वविद्यालय ने एक अनुसंधान में यह दावा किया था कि इससे प्रदेश की आर्थिकी में पांच हजार करोड़ का बढ़ावा होगा। जिस पर कोई कदम नहीं उठाये गये। ऐसे ही कई अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय के रहे हैं। प्रदेश में जियोट्राफा के उत्पादन से डीजल तैयार करने की तीस करोड़ की योजना केंद्र से मिली थी। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर के निचले क्षेत्र शामिल किये गये थे। ऊना में कुछ लोगों की निजी भूमि पर भी जियोट्रोफा की खेती कर दी गयी। यदि उस योजना पर ईमानदारी से अमल किया जाता तो उसी से प्रदेश का नक्शा बदल जाता। लेकिन इसमें ठेकेदारी और कमीशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिये शुरू होते ही इसका गला घोंट दिया गया। विधानसभा में इस पर आये सवालों पर चुप्पी साध ली गयी। इस योजना का जिक्र इसलिये कर रहा हूं ताकि आज नेतृत्व भविष्य के नाम पर वर्तमान को गिरवी रखने की मानसिकता से बाहर निकल कर ईमानदारी से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देकर उसे खेत तक ले जाने का ईमानदारी से प्रयास करे। यदि कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर टूरिज्म विलेज बसाने का प्रयास किया जायेगा तो उसके परिणाम कर्ज के चक्रव्यूहं को और मजबूत करना होगा।

इस्लामोफोबिया के मामले में भारत पर आरोप लगाने से पहले पश्चिमी जगत अपने गिरेबान में झांके

गौतम चौधरी

हमें अपने देश के हालात और सामाजिक स्थितियों की तुलना पश्चिम के देश या फिर दुनिया के अन्य देशों से नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब तक हम अपनी तुलना किसी अन्य नहीं करते तब तक वास्तविक हालात का आकलना नहीं हो पाता है। इस आलेख में आज हम पश्चिम के देशों में व्याप्त इस्लामोफोबिया पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही भारत में मुसलमानों की स्थिति और भारतीय समाज में मुसलमानों की अहमियत की पड़ताल भी करेंगे। मसलन, इधर के दिनों पश्चिमी जगत में बड़ी तेजी से इस्लामोफोबिया बढ़ा है। इसके कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं।

हाल के वर्षो में, पश्चिमी देशों में इस्लामोफोबिया का बढ़ना चिंता पैदा करने लगा है। खासकर तब, जब कुछ गुप्त उद्देश्यों वाले संगठनों के इशारे पर, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिल रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम व्यक्तियों को केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर नौकरी के अवसरों या पदोन्नति से वंचित किया गया। इस्लामोफोबिया के कारण कुछ लोगों को महत्वपूर्ण यात्रा से वंचित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुसलमान होने के कारण पूर्व में ट्रम्प प्रशासन द्वारा कुछ मुस्लिम बच्चों के साथ भेदभाव किया गया। ये सारे काम इस्लामोफोबिया के उदाहरण हैं।

इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) जैसे पश्चिम आधारित संगठन अक्सर भारत पर इस्लामोफोबिक नीतियों को अपनाने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी जगत के इस्लामोफोबिया और भारत में मुसलमानों की स्थिति के बीच तुलना करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सांप्रदायिक घटनाएं नहीं घट रही है। यहां भी दो समुदायों के बीच लड़ाई होती है। खासकर हिन्दू और मुसलमान कई स्थानों पर आपस में जूझते देखे जाते हैं। यह गतिरोध आम बात है लेकिन भारत में इस प्रकार की घटनाओं के बीच प्रशासन की भूमिका तटस्थ देखने को मिलती है। यही नहीं भारत का कानून और न्याय प्रणाली भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से परहेज करता है, जबकि इन दिनों पश्चिम में इस्लामोफोबिक का असर उनके प्रशासन और कानूनी संस्थाओं में भी देखने को मिल रहा है। यह चिंता का विषय है।

कई स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय एजेंशियों का दावा है कि पश्चिमी इस्लामोफोबिया की तुलना में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बेहद कम है। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों यह लगातार बढ़ रहा है। यह आंशिक रूप से भारत में मुसलमानों की ऐतिहासिक उपस्थिति और धार्मिक सह-अस्तित्व की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के कारण है। इसके अतिरिक्त, भारतीय समाज के सांप्रदायिक सद्भाव और विविधता के प्रति सम्मान पर जोर ने इस्लामोफोबिया को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भेदभाव और पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद हैं, जो स्वीकृति और समझ को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भारत के धार्मिक सहअस्तित्व का एक उदाहरण लखनऊ शहर का है, जो अपनी समृद्ध इस्लामी विरासत और जीवंत हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक एकता के लिए जाना जाता है। यह शहर कई ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का घर है, जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा और भूल भुलैया, जो सभी धर्मो के आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। स्थानीय लोगों ने इस विविधता को अपनाया है और एक-दूसरे के त्योहारों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे हिंदू मुसलमानों के त्योहार ईद में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और मुस्लिम दिवाली उत्सव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह समावेशी वातावरण ने मजबूत अंतर-धार्मिक संबंधों को बढ़ावा दिया है और यह सहिष्णुता और सद्भाव की शक्ति का प्रमाण भी है।

भारतीय एक-दूसरे की मान्यताओं को समझने और उनका सम्मान करने लगे हैं, जिससे एक ऐसा माहौल बन गया है, जहां व्यक्ति भेदभाव के डर के बिना अपनी धार्मिक प्रथाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इस सह-अस्तित्व ने न केवल देश के सांस्कृतिक ताने-बाने को समृद्ध किया है, बल्कि शांतिपूर्ण धार्मिक एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे दुनिया भर के अन्य समुदायों के लिए एक चमत्कारिक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। इस्लामोफोबिया से निपटने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्कूल और संस्थान इस्लाम और उसके अनुयायियों के बारे में सटीक और निष्पक्ष जानकारी को बढ़ावा देते हैं। भारत में इसकी कमी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मीडिया आउटलेट्स को रूढ़िवादिता को चुनौती देते हुए और गलत धारणाओं को दूर करते हुए, मुसलमानों का निष्पक्ष और संतुलित चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास भारतीय समावेशी राष्ट्रवादी समाचार माध्यम ने मानों अपना कर्तव्य तर लिया हो। अंततः, इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई में बेहतर परिणाम के लिए अधिक समावेशी और स्वीकार्य समाज बनाने की जरूरत है। दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। जो संगठन भारत में इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानी को प्रचारित करने के लिए पश्चिमी देशों की धरती का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

78वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के विकास को आकार देने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश को विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से भविष्य के लक्ष्यों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

आज वो शुभ घड़ी है, जब हम देश के लिए मर-मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्ते पर चढ़ करके भारत माँ की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करते हैं।

प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोये हैं, सम्पत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी बारम्बार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

विकसित भारत 2047, ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं हैं, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई intellectual debate नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है।

ढाई करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है। तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ जाता है। स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संबंध में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे, मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है।

जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं।

हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है। One district one product का माहौल बना है। अब one district one product को one district का one product export कैसे हो उस दिशा में सभी जिले सोचने लगे हैं।

देश गर्व करता है आज जब fintech की सफलताओं को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है। तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है।

यही देश है जब आतंकवादी हमें मार के चले जाते थे। आज जब देश की सेना Surgical Strike करती है, तो उस देश के नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता है।

मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, reforms के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो pink paper के editorial के लिए सीमित नहीं है। reforms का हमारा मार्ग एक प्रकार से growth की blue print बना हुआ है।

हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेकविद रिफॉर्म्स किए। और आज उसके कारण हमारे बैंक विश्व में जो गिने चुने मजबूत बैंक हैं उसमें भारत के बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना तब formal economy की ताकत भी बढ़ती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई-बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी-पटरी वाले लाखों भाई-बहन आज बैंक के साथ जुड़कर के अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं

हमारा एक ही संकल्प होता हैं- Nation First- राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं।

आज हमने गवर्नेंस के model को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी के पास जाती है, उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है, उसके घर पानी पहुंचाती है, उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद नौजवान के skill development के लिए अनेक कदम उठा रही है।

आज विश्वभर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए Golden Era है। यह हमारा स्वर्णिम कालखंड है।

आज Tourism, MSMEs, Education, Health sector, Transport sector, खेती और किसानी का सेक्टर, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की इमेज practices को आगे रखते हुए अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं।

बीते वर्षों में Women led development Model पर हमने काम किया है। Innovation, Employment, Entrepreneurship, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं।

आज 10 साल में हमारी 10 करोड़ बहनें women self help में जुड़ी है। वे बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की गारंटी ले करके आती हैं। मेरी सामान्य परिवार की माताएं-बहनें लखपति दीदी बनती हैं, मेरे लिए ये भी उतनी ही गर्व की बात है।

अब हमने self help group को 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये देने का निर्णय किया है। अब तक 9 लाख करोड़ रुपये बैंकों के माध्यम से हमारे इन women self help groups को मिले हैं और जिसकी मदद से वो अपने अनेकविद् कामों को बढ़ा रहे हैं।

जब हम Working women के लिए paid maternity leave 12 हफ्ते से बढ़ाकर के 26 हफ्ते कर देते हैं। तब सिर्फ नारी सम्मान ही नहीं करते हैं बल्कि, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते हैं और उसकी गोद में जो बच्चा पला है उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मां की जो जरूरत है, उसमें सरकार रूकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से हम निर्णय करते हैं।

दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं, हमे गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं-बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा।

मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे C.E.O. आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं।

स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत reform किए हैं। जिन बंधनों में स्पेस सेक्टर को बांध कर रखा था, उसे हमने खोल दिया है। आज सैंकड़ों Startups स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं।

पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, Government connectivity हो, गांव-गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर-सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बने हों, दो लाख पंचायतों तक Optical fiber network पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, चार करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, तीन करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो।

हमारा पूर्वी भारत-नॉर्थ ईस्ट उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाने लगा है और हमने ये जो कायाकल्प किया है, उसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि हम समाज के उन वर्गो तक पहुंचे हैं।

जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो देश के लिए बहुत देता है, मध्यम वर्गीय परिवार को Quality of Life, की स्वाभाविक अपेक्षा रहती है। मैंने 2047 के लिए विकसित भारत का जो सपना सपना देखा है उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानवीय के जीवन में सरकार की दखलें कम हों।

लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, उस दिशा में हमने डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों के जंजाल कें अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े।

सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे, आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं, नागरिक को न्याय, इस भाव को हमने प्रबल बनाया है।

आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान नई सिद्धियों को चूमना चाहता है। नए-नए शिखरों पर वो कदम रखना चाहता है। और इसलिए हमारी कोशिश है हर सेक्टर में कार्य को हम गति दें, तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम हर सेक्टर में नए अवसर पैदा करें।

मुझे विश्वास है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के अवसर पर हमने काम किया है। प्रति व्यक्ति आज आय दोगुनी करने में हम सफल हुए हैं। Global growth में भारत का योगदान बड़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है, पहले से दोगुना पहुंचा है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। मुझे विश्वास है भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है।

मैं जब कोरोनाकाल को याद करता हूं। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच सबसे तेजी से इकोनॉमी को बेहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है। तब लगता है कि हमारी दिशा सही है।

जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने-अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान हैं।

जब जात पात मत पंथ से ऊपर उठकर हर घर तिरंगा फहराया जाता है, तब लगता है कि देश की दिशा सही है। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है, न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय हैं।

60 साल बाद आपने लगातार तीसरी बार हमें देश सेवा का मौका दिया है। मेरे 140 करोड़ देशवासी आपके इस आशीर्वाद में मेरे लिए एक ही संदेश है जन-जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ लेकर के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना। मैं कोटि-कोटि देशवासियों का सर झुकाकर के आभार व्यक्त करता हूं,

आज नई शिक्षा नीति में कई राज्यों ने अच्छे initiative लिए हैं। नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश के टैलेंट को रूकावट नहीं आनी चाहिए।

बिहार का हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अभी-अभी हमने नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उसे ले करके बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा।

हम Industry 4.O को ध्यान में रख करके हम skill development चाहते हैं। skill development में भी हमने नए model तय किए हैं। हमने जनभागीदारी को जोड़ा है ताकि तुरंत requirement के अनुसार skill development हम कर सकें। मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत Industrial manufacturing का हब होगा, दुनिया उसकी तरफ देखती होगी।

विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में Science और Technology का महात्मय बढ़ता चला जा रहा है। हमें Science पर बहुत बल देने की आवश्यकता है। और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल, कॉलेज के अंदर Science और Technology के प्रति एक नई रूचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है।

आज भी हमारे देश में Medical Education के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। वो ज्यादातर मध्यम वर्ग परिवार के हैं। उनके लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं और तब जा करके हमने पिछले 10 साल में Medical सीटों को करीब-करीब एक लाख कर दिया है। हमने तय किया है कि अगले 5 साल में, Medical line में 75 हजार नई सीटें बनाई जाएंगी।

हमारी कृषि व्यवस्था को transform करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम उसको transform करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं। आसान ऋण दे रहे हैं, किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं।

आज दुनिया की स्थिति मैं देखता हूं, पूरा विश्व Holistic Health Care की तरफ मुड़ रहा है और तब उनको Organic Food जो उनकी प्रथम पसंद बनी है, आज विश्व के लिए Organic Food का अगर कोई Food Basket बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है।

मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी धमक लेकर के पहुंच रहे हैं। खिलौने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए हैं। कोई एक जमाना था, हम मोबाइल फोन इम्पोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन के Manufacturing का Ecosystem बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है और आज हम मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है।

भविष्य के साथ Semiconductor जुड़ा हुआ है। आधुनिक टेक्नोलोजी जुड़ी हुई है, AI जुड़ा हुआ है। हमने Semiconductor मिशन पर काम शुरू किया है और उपकरण में Made in India Cheap क्यूँ न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे, टेलेंट यहां है। सारे इस प्रकार के रिसर्च के काम हिन्दुस्तान में होते हैं तो अब प्रोडक्शन भी हिन्दुस्तान में होगा। Semiconductor का काम भी हिन्दुस्तान में होगा।

आज Defence Manufacturing में, भारत की पहचान बनीं है और मैं खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी Defence की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज हम Defence के Equipment Manufacturing कर रहे हैं, और Export भी करने लगे हैं। दुनिया में Defence Hub Manufacturing के रूप में हम धीरे-धीरे उभर रहे हैं।

हम manufacturing क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि बेरोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज PLI Scheme को बहुत बड़ी सफलता मिली है। FDI Reforms उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। MSME's को बहुत बड़ा बल मिला है।

मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं। विश्वभर के निवेशक हैं, वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी golden opportunity है।

भारत अपनी best quality के लिए पहचाना जाए ये बहुत जरूरी है। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन का क्षेत्र design in India इस पर हमें बल देना है। हमें कोशिश करनी है कि Indian Standard International Standard बनने चाहिए।

मैं देख रहा हूं gaming की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम gaming की दुनिया में बहुत नई talent को लेकर के आ सकते हैं।

आज मैं लालकिले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। जी-20 देश के समूह जो नहीं कर पाए वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है, हिन्दुस्तान ने करके दिखाया है। Paris accord के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला जी-20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिन्दस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत मिलने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला है, विशेषकर के मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा, जब उसका बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा।

हम Green Hydrogen Mission लेकर के एक global hub बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई हैं, बहुत तेजी से उसका implementation का काम हो रहा है और भारत green hydrogen एक new energy की दिशा में हम जाना चाहते हैं।

आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया है। मैं, देश के सभी एथलीट्स को, सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं। भारत को, किसी को भी hospitality का सार्म्थय सबसे ज्यादा है। अगर यह सिद्ध हो चुका है, तो साथियों हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो Olympic होगा, वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। यह हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बनें। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसे जज़्बात रखता है उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से कौन अधिक कौन हो सकता है।

हम संकल्प के साथ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं जब तक खुद का भला न हो, तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसे विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा।

मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम अपनी नेक नियत से, अपनी ईमानादारी से, राष्ट्र के प्रति समर्पण से, हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी उनके भी दिल जीत करके, हम देश को आगे बढ़ाने के संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, यह मैं विश्वास देना चाहता हूं।

चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं और जैसे-जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे-जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं और मुझे उसका भलीभांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं भारत का विकास किसी के लिए संकट ले करके नहीं आता है।

मैंने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। मैं जानता हूं, इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता है। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी।

देश में, इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमामंडन कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खासकर के 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चलें।

अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। देशवासियों को संविधान में निर्दिष्ट कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरुरी है और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी हैं, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी हैं, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी हैं, राज्य सरकार के मुलाजिम के हैं।

देश की मांग है, कि अब देश में एक Secular Civil Code हो, हमने Communal Civil Code में 75 साल बिताएं हैं। अब हमें Secular Civil Code की तरफ जाना होगा, और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहें हैं, सामान्य नागरिकों को दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्धति मिलेगी।

मैं देश में एक चिंता के बारे में हमेशा कहता हूं परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में, शुरूआत में जनप्रतिनिधि के रूप में एक लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक background न हो।

बार-बार चुनाव, इस देश की प्रगति में रूकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज किसी भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है। ऐसे में One Nation One Election के लिए देश को आगे आना होगा। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। इस पर देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीति दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक committee ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है।

मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे term में देश तीसरी Economy तो बनेगा ही, लेकिन मैं तीन गुना काम करूंगा। मैं देशवासियों को आहवान करता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो सपनें देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाएं, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरूषार्थ को जोड़े और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना करके रहें।

साहसिक फैसलों से पूरा होगा समृद्ध-आत्मनिर्भर हिमाचल का संकल्प

-ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू-
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह हमारे लिए बहुत गर्व और हर्ष का दिन है क्योंकि इसी शुभ दिन एक लम्बे संघर्ष के उपरान्त भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों तथा राष्ट्र-निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ हैं जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप हमारा देश आज अपनी मज़बूत और विशेष पहचान बना पाया है।

हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी आज़ादी के आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर दमनकारियों का डटकर सामना किया। देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए विकट परिस्थितियों में हमारे वीर सपूतों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए गए।

हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के पहले परमवीर चक्र से प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को नवाज़ा गया। हिमाचल प्रदेश से ही संबंध रखने वाले कर्नल डी.एस. थापा, कैप्टन विक्रम बत्तरा तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हिमाचल के नौजवान देश की सेनाओं का हमेशा महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं और हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोगों के बुलंद हौसलों और मेहनत के कारण हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है।

प्रदेश की जनता के भरपूर सहयोग और आशीर्वाद से 11 दिसम्बर, 2022 को कांग्रेस सरकार ने राज्य में जन सेवा का दायित्व संभाला। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मुझे सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर प्राप्त हुआ। 20 महीने के छोटे-से कार्यकाल में हमने राजनीतिक, आर्थिक और आपदा के मोर्चों पर तीन-तीन चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया।

मैं सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखा और भरपूर सहयोग दिया। प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कई साजिशें रची गईं। चुनी हुई प्रदेश की सरकार को धनबल और बेईमानी के सहारे गिराने के प्रयास भी बहुत किए गए। प्रदेश पर उप-चुनावों का आर्थिक बोझ पड़ा और विकास परियोजनाओं की गति रोकने के भी प्रयास किए गए। लेकिन प्रदेशवासियों ने उन्हें नाकाम कर दिया तथा लोकतंत्र को मजबूत करते हुए धनबल को हराकर जनबल की विजय का परचम लहराया।

हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले दस वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल हो। हमने आबकारी नीति में बदलाव लाने जैसे कई साहसिक फैसले लिए हैं जिनसे केवल एक वर्ष में ही 2200 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश के हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की है। इन प्रयासों से अडाणी पॉवर्स और वाइल्ड लावर हॉल जैसे मामलों का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है।

हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है, जहां लोग अमीर हैं पर सरकार गरीब है। इसका कारण पिछली सरकार ने अमीर-गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। साथ ही कुछ ऐसे फैसले लिये जिनसे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ गया। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी दोनों के बिल जीरो कर दिए। जो व्यक्ति जरूरतमंद है उसे यह सुविधा मिले, इसका हमारी सरकार विरोध नहीं करती। लेकिन सम्पन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर इस साल 780 करोड़ रुपये और पानी का बिल जीरो करने से 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

भारत का वित्त आयोग हर पांच साल के लिए ऐसे प्रदेशों को विशेष सहायता देता है जो रेवेन्यू सरप्लस नहीं होते यानी उनमें राजस्व पैदा करने के साधन कम होते हैं। देश में राज्यों का गठन सम्पूर्ण आर्थिक इकाइयों के तौर पर नहीं किया गया है इसलिये इन्हें राजस्व सरप्लस एरिया की तरह देखना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार ने विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया है और हमारे लिए राजस्व घाटा अनुदान का प्रावधान किया है।

15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान में कटौती कर प्रदेश के साथ अन्याय किया। हमने प्रदेश के हित में इस मामले को 16वें वित्त आयोग के सामने प्रमुखता से रखा है। वर्ष 2021-22 में यह ग्रांट 10 हजार 249 करोड़ थी, जो वर्ष 2025-26 में घटकर 3 हजार 257 करोड़ रुपये रह जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आने वाले साल में प्रदेश को विकास के लिए लगभग 7 हज़ार करोड़ रुपये कम मिलेंगे। पिछली सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया। हमने इस मामले को 16वें वित्त आयोग के सामने प्रमुखता से रखा है।

हिमकेयर योजना के दुरुपयोग के कई मामले सामने आये हैं। बहुत से निजी अस्पतालों ने इसे पैसा कमाने का धंधा बना लिया था। इसलिए हमने 147 निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। निजी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा को बहाल रखा गया है।

वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हमें अपने तौर-तरीके बदलने की ज़रूरत है। इस साल प्रदेश के 99 प्राइमरी स्कूलों और 10 मिडल स्कूलों में शून्य नामांकन थे, जिन्हें बन्द करने का निर्णय लिया गया है। हमने दो किलोमीटर दायरे के प्राइमरी स्कूलों और तीन किलोमीटर के दायरे के मिडल स्कूलों में पांच और इससे कम विद्यार्थी संख्या होने की स्थिति में इनका निकटतम विद्यालय के साथ विलय करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमने इस आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग खोला है। आयोग ने कुल लम्बित 2,983 पदों के परिणामों में से 1841 पदों के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए है। चार साल से लटके जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 817 का केस भी हमारी सरकार ने मजबूती के साथ लड़ा और न्यायालय से फैसला आने के बाद इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। बाकी लंबित परीक्षा परिणामों को भी जल्दी घोषित करने के प्रयास किए जा रहे है।

पिछले वर्ष की तरह इस बरसात में भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कई बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में हमने खोए है, जिन्हें मै श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मै विश्वास दिलाता हूं कि दुख की इस घड़ी में हम आपदा प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और एक-एक परिवार को फिर से बसाना हमारा संकल्प है। हर प्रभावित परिवार को फौरी राहत के रूप में 50 हज़ार रुपये दिए गए हैं। उन्हें तीन महीने तक किराए पर मकान के लिए शहरी क्षेत्र में 10 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 5 हज़ार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। प्रभावितों को मुत राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

हमारी सरकार की पहली जिम्मेदारी समाज के संवेदनशील वर्गों का संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू कर 6 हज़ार बच्चों को 'चिल्ड्रन आफ द स्टेट' के रूप में अपनाकर सरकार इनकी पढ़ाई, जेब खर्च का जिम्मा उठा रही है।

अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रहीं लगभग 2. 37 लाख महिलाओं को भी इसके दायरे में लाकर मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है।

प्रदेश के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना बहाल कर 1.36 लाख से अधिक कर्मचारियों और उनके लाखों परिजनों को लाभान्वित किया है। लेकिन कर्मचारियों के एनपीएस के लगभग 9 हजार 200 करोड़ रुपये अभी भी केन्द्र सरकार के पास फंसे हैं।

अपने एक और चुनावी वायदे को पूरा करते हुए हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत ई-टैक्सी खरीदने, निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। तीसरे चरण में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना भी लागू की गई है जिसके अंतर्गत लगभग 50 हजार किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य है।

प्रदेश के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेज़ी माध्यम शुरू करने की गारंटी को हमने पूरा किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से हमने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं।

हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामले गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए नि:शुल्क इलाज और मुत दवाइयां प्रदान करने का निर्णय लिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 462 पद और आई.जी.एम.सी., शिमला व अटल सुपर स्पेशिल्टी आयुर्विज्ञान संस्थान, चमियाना, में 489 पद भरने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगभग 2700 पदों को भरा जा रहा है।

बागबानी क्षेत्र का हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है। बागबानों के हित में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है। इस साल सेब सीज़न के दौरान यूनिर्वसल कार्टन का प्रयोग शुरू किया गया है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए 153 करोड़ रुपये जारी किए गए है जिसमें पिछली सरकार की 90 करोड़ रुपये की देनदारी भी शामिल है। इस साल भी सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों को 12 रुपये के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला हिमाचल देश का एकमात्र राज्य है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में प्रदेश में 6 ग्रीन कोरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। नालागढ़ में ऑयल इंडिया कम्पनी की भागीदारी से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए एक मैगावाट का प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऊना जिला के पेखूबेला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की गई है जिससे सालाना 19 करोड़ 17 लाख रुपये के राजस्व लाभ का अनुमान है। अघलौर में 10 मेगावाट और भंजाल में पांच मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। इन परियोजनाओं के संचालन से प्रदेश सरकार को 11 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

प्रदेश सरकार पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवा रही है जिससे पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरा उप-मण्डल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट निर्मित किए जा रहे हैं और रोप-वे निर्माण को भी गति दी जा रही है।

राज्य सरकार सड़कों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों तक रोजाना लाखों यात्रियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। निगम को इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 517 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

हमारी सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में रोज़गार के 31 हजार से अधिक अवसर सृजित किए हैं। इसकी तुलना में, पूर्व भाजपा सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में केवल 20 हजार नौकरियां दी थीं जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव-पेचों में उलझी रहीं।

प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर 1,87,500 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। इस व्यवस्था से आम आदमी को भूमि से जुड़े मामलों में बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिली है।

मै प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने का सपना साकार कर रही है। पिछली भाजपा सरकार प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियों का बोझ छोड़ कर गई। यही वजह है कि राज्य सरकार को कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आज हालात ये हैं कि 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये, पैंशन पर 17 रुपये, ब्याज पर 11 रुपये, कर्ज अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपये और बचे हुए 28 रुपये पूंजीगत व्यय और अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के विकास और जनकल्याण में खराब आर्थिक स्थिति को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा।

मैं एक बार फिर समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

जय हिन्द, जय हिमाचल...!

सूचना-सम्पर्क-सेवा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश

78वें
स्वतंत्रता दिवस
की सभी
प्रदेशवासियों को
अनंत शुभकामनाएँ

प्रगतिशील वर्तमान,
बेहतर और उन्नत कल
संकल्प है प्रबल,
बनाएंगे उज्ज्वल हिमाचल।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की निष्ठा, समर्पण व कर्तव्यबोध से हम सब मिलकर इस प्राकृतिक सौंदर्य से अलंकृत और पर्यावरण संरक्षण की अग्रदूत देवभूमि हिमाचल को नव आयामों तक ले जाएंगे।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

जारीकर्त्ता: सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार www.himachalpr.gov.in HimachalPradeshGovtIPRDept diprhimachal dprhp

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

कर्मचारियों के देय भत्ते जल्द न दिए तो अपना सकते हैं आन्दोलन का रास्ता:प्रकाश बादल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ द्वारा कर्मचारियों के देय वेतन भत्ते न देने के विरोध में हाल ही में की गयी प्रेस वार्ता के बाद अब हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों ने अपना मोर्चा खोला है। महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल और वन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने एक संयुक्त प्रैस वार्ता में बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षो से उन्हे देय भत्ते न मिलने से कर्मचारियों में निराशा है। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने बताया कि कर्मचारियों का 12 प्रतिशत डीए सरकार ने अब तक अदा नहीं किया है और पे रिविज़न का एरियर भी बकाया है। प्रकाश बादल ने यह भी बताया कि एक तरफ सरकार तरह-तरह के शुल्क लगा रही है, वहीं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों की देय वृद्धि उन्हें जारी नहीं कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। प्रकाश बादल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार द्वारा गत दिवस कर्मचारियों और पेंशनरों के देय वेतन भत्ते जारी न करने हेतु की गयी प्रेस वार्ता का स्वागत करते हुए कहा है कि वन विभाग के कर्मचारी सचिवालय सेवाएं संघ के 21 अगस्त को होने वाले जनरल हाऊस में भाग लेगा और अपनी मांगों को लेकर सचिवालय सेवाएं संघ के साथ चलेगा। प्रकाश बादल ने यह भी बताया की प्रदेश की नौकरशाही मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों के भत्तों की देनदारी को लेकर गुमराह कर रही है, जबकि दूसरी ओर सरकार में फ़िजूल खर्ची रोकी नहीं जा रही। प्रकाश बादल ने अपने ब्यान में आगे कहा है कि छोटे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री और सरकार से सीधा संवाद न होने के कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जहाँ नौकरशाही कर्मचारियों की देनदारियों के भ्रामक आंकड़े मुख्यमंत्री को बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री और सरकार के बीच संवाद के रास्ते लगभग बंद है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का चुनाव होने के बाद भी कर्मचारियों को जेसीसी और वार्तालाप के लिए न बुलाया जाना निराशाजनक है। प्रकाश बादल ने यह भी बताया कि संवादहीनता के कारण हिमाचल के कर्मचारी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग नहीं रख पा रहे हैं और न ही कर्मचारियों के पत्रों का सरकार द्वारा कोई उत्तर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ नौकरशाही कर्मचारियों के भत्तों में अडंगा लगा रही है। प्रैस वार्ता में यह भी बताया की यदि कर्मचारियों के देय भत्ते नहीं दिए गए तो कर्मचारी आगामी रणनीति के तहत आन्दोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।

प्रकाश बादल ने हिमाचल के सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों से एक साझा मंच बनाने का भी आग्रह किया ताकि सरकार के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके । उन्होंने यह भी बताया की कर्मचारियों के वेतन भत्ते न मिलने का मुख्य कारण कर्मचारियों के खेमों में बंटे होना है। कोई भी कर्मचारी संगठन कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष नहीं उठा रहा है । ऐसे में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार के समक्ष अपनी मांगे पुरजोर तरीके से रखने के लिए वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने खुशी ज़ाहिर की है और इसकी सराहना की है । उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि सभी मतभेद दूर करके कर्मचारियों को एक जुट होकर अपनी मांगे सरकर के समक्ष रखने की रणनीति तय करें। कर्मचारियों का, सरकार द्वारा वेतन भत्ते न दिए जाने पर रोष बढ़ता जा रहा है । बादल ने यह भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री कर्मचारियों को निराश नहीं करेंगे और जल्द ही कर्मचारियों के देय वेतन भत्ते जारी करने के आदेश जारी करेंगे।

फील्ड में भेजे जाएं दफ्तरों में काम करने वाले फारेस्ट गार्ड, बीओ एवं रेंजर

हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने प्रेस वार्ता में बताया कि वन विभाग में वर रक्षक, बीओ एवं रेज अफसर को विशेष रूप से लाखों रूपए ट्रेनिंग के द्वारा यूं तो जंगलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षो से तीन सौ से भी अधिक वन रक्षकों को दफ्तरों में तैनाती दी गयी है। यह न केवल सरकारी धन का दरुपयोग है, बल्कि हिमाचल के वनों में खाली पड़ी बीटों के लिए भी चिंताजनक है। प्रकाश बादल ने अपने ब्यान में यह भी बताया कि एक तरफ जो वन रक्षक फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको पांच से छ: बीटों का चार्ज दिया गया है, जबकि कुछ लोग सरकारी नियमों को ताक पर रख कर दफ्तरों में बाबू का काम दिया गया है, जिससे न केवल सरकारी धनराशी का दरुपयोग हुआ है, बल्कि दफ्तरों में काम कर रहे वन रक्षकों के कारण फील्ड की सैंकड़ों बीटें खाली पड़ी हैं और अधिकतर वनरक्षकों के पास एक से अधिक बीटों का चार्ज है। इसी प्रकार लगभग सौ वन रक्षक वन विभाग में स्पेशल डयूटी पर दफ्तरों में तैनात हैं और कई रेंज अफसर भी दफ्तरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार फील्ड स्टाफ को दफ्तरों में लगाया जाना सरकारी धन का दरुपयोग है। दूसरी तरफ वन विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों को लम्बे अरसे से न भरे जाने के कारण विभाग में लगभग 150 क्लर्क/जेओएआईटी के पद खाली हैं और सौ से भी अधिक सीनियर असिस्टेंट के पद खाली है, जिन्हें भरने के लिए वन विभाग ने कोई विशेष रूचि नहीं दिखाई है। प्रकाश बादल ने यह भी बताया कि इससे पहले समय-समय पर वो सरकार और विभाग को लिखते आये हैं कि वन विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की रिक्तियां जल्द भरी जायें और फील्ड स्टाफ को फीड में तैनात किया जाए। बादल ने यह भी बताया की दफ्तरों में तैनात फील्ड कर्मचारियों के कारण अतिरिक्त कार्यभार का बोझ ढो रहे फील्ड कर्मचारी भी मानसिक तनाव में हैं बल्कि कई बार अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण उन्हें वन माफियाओं से लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। होशियार सिंह काण्ड इसका ज्वलंत प्रमाण है। बादल ने वन विभाग की फील्ड स्टाफ एसोसिएशन से भी आग्रह किया है कि वो भी सरकार के समक्ष दफ्तरों में काम कर रहे फील्ड स्टाफ को फील्ड में तैनात करने का आग्रह करें। प्रकाश बादल ने यह भी बताया कि उन्हें वन विभाग के नवनियुक्त वन बल मुखिया डॉ. पवनेश से भी वो जल्द बैठक करेंगे और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। यदि जल्द फील्ड स्टाफ को फील्ड में तैनाती नहीं दी गयी तो हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी न्यायालय की शरण लेने पर भी विवश होंगे।

सैजल ने सुक्खू पर लगाया लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ. राजीव

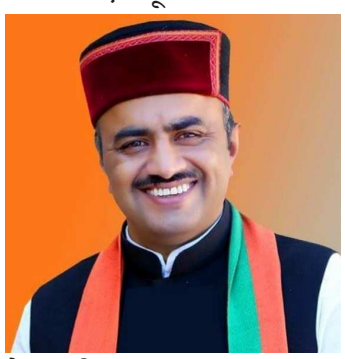

सैजल ने सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की सरकार के उपर सवालिया निशान लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वायत संस्थाएं पंचायतीराज, नगर परिषद एवं नगर निगम में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही हैं अपने राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए संविधान में संशोधन करते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का षड़यंत्र हिमाचल प्रदेश में सब तरफ चला हुआ है और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सोलन नगर निगम का चुनाव है। सोलन में मेयर के पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाती है और अधिसूचना करने के बाद शहरी विकास विभाग एक असंवैधानिक अधिसूचना करता है जिसके अनुसार वोट डालने वाला पार्षद वोट दिखाकर डालेगा।

डॉ. राजीव ने कहा कि यदि चुने हुए पार्षद वोट दिखाकर डालेंगे तो वोटिंग का अर्थ ही समाप्त हो गया और वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में हाथ खड़े करके भी चुनाव करवाया जा सकता है।

डॉ.राजीव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव आयोग भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं जो अत्यंत दुखदायी है और बड़े-बड़े अफसरान कांग्रेस के ईशारे के उपर इस प्रकार की गलत अधिसूचना करके लोकतांत्रिक मूल्यों को कांग्रेस पार्टी के हित में समाप्त कर रहे हें।

डॉ. राजीव ने कहा कि मेयर के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद यह अधिसूचना करना चुनाव की मूल भावना को ही समाप्त करता है।